किधर जा रहे हो,कॉमरेड?

कन्हैया कुमार : उतरता बुखार

सीपीआई अपने पुराने ढ़र्रे पर ही है,

भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस, राजद ऐसी शक्तियों के सहयोग में खड़ा होगी!

कुछ भी नया व अप्रत्याशित नहीं है!

सीपीएम में कांग्रेस और भाजपा विरोधी पार्टियों से राजनीतिक रिश्ते पर तीखी बहस हुई।

बहस बाहरी दायरे में भी चर्चा में रही। सीपीएम ने कांग्रेस सहित राजद ऐसी शक्तियों के साथ राजनीतिक गठजोड़ में जाने का फैसला नहीं लिया,बात ऐसी ही सामने आ रही है।

भाकपा-माले के राजनीतिक कार्यनीति की दिशा में बड़े बदलाव की बात सामने आ रही है!

फासीवाद/भाजपा को हराने के लिए राजद ऐसी शक्तियों के साथ चुनावी मोर्चे में जाने का साफ संकेत है।

अभी-अभी जनाधिकार पदयात्रा के अंत में ऐतिहासिक गांधी मैदान में महासम्मेलन में महासचिव दीपांकर भट्टाचार्या के भाषण ने तो साफ कर दिया है!

यह पूरी कवायद बिहार में राजनीतिक कार्यनीति की दिशा को सामने लाने,उस दिशा में अपनी कतार को गोलबंद करने और चुनावी मोर्चा में दावा जतलाने का मामला भर था!

उनके भाषण के कुछ अंश पर जरूर ही गौर किया जाना चाहिए-

"भाजपा ऐसी पार्टी है जो चुनाव हारकर भी सता हथिया लेती है। बिहार में चुनाव हारने के बाद भी उसने चोर दरवाजे से सत्ता हथिया ली। इसलिए जहां भी चुनाव हो, भाजपा को खदेड़ बाहर करना व उसे सत्ता से बेदखल करना आज हम सबका प्रमुख कार्यभार है।" .....

"कुछ लोग 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में वामपंथ की गलती का सवाल उठाते हैं। उस चुनाव में बिहार की जनता भाजपा के खिलाफ जनादेश दिया था। उसी से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन हमने देखा कि कुछ ही दिन में वे भाजपा के साथ जा मिले और आज बिहार में भाजपा की सत्ता चल रही है, जिसके सामने नीतीश कुमार ने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है। 2015 का मोर्चा नकली मोर्चा था। नीतीश कुमार सत्ता के भूखे हैं। कभी जयप्रकाश तो कभी लोहिया का नाम लेते हैं, लेकिन भाजपा की गोद में सरेंडर कर गए हैं। ऐसा कोई मोर्चा नहीं बन सकता जिसमें लाल झंडा न शामिल हो। बिहार के मजदूर-किसान, अकलियत, मजदूर-किसान, छात्र-नौजवान इस मोर्चा का निर्माण करेंगे और भाजपा के साथ कदम-कदम पर लड़ेंगे।"

खैर महाधिवेशन के दस्तावेज कुछ भी हो,

जोर कहीं और भी हो,

लेकिन राजनीतिक व्यवहार और महासचिव के भाषण में जोर का बिंदु और प्रमुख कार्यभार स्पष्ट हो रहा है!

खैर,राष्ट्रीय परिस्थिति के कुछ पहलू पर गौर करते हुए बात आगे बढ़ाई जाए!

जब बिहार में राजद ऐसी शक्तियों से चुनावी मोर्चा बनाना और चुनाव में भाजपा को हराना प्रमुख कार्यभार हो जाए तो इस पहलू पर गौर करना जरूरी हो जाता है!

फासीवादी हमले का महत्वपूर्ण आयाम है-ब्रह्मणवादी प्रतिक्रिया और सवर्ण दबदबा!

दलितों-वंचितों पर हमले के साथ ही सामाजिक न्याय के मोर्चे पर हासिल उपलब्धियां भी छीनी जा रही है!

खासतौर पर,रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या और महाराष्ट्र में अंबेडकर भवन स्मारक के तोड़े जाने के खिलाफ दलितों-वंचितों की सड़कों पर राष्ट्रव्यापी सक्रियता सामने आई।

एक नारा भी चल निकला,जय भीम-लाल सलाम!

कहिए तो इस दौर में नरेन्द्र मोदी के फासीवादी निजाम के खिलाफ दलितों-वंचितों का जागरण रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या,ऊना,सहारनपुर के रास्ते 2अप्रैल ऐतिहासिक भारत बंद तक पहुंच चुका है।

लेकिन इसी बीच जय भीम-लाल सलाम का नारा गुम होता हुआ दीख रहा है!

जब कैम्पसों से खेत-खलिहानों तक दलितों-वंचितों के बीच से संघर्ष की नई शक्तियां उभर रही हैं,

सामाजिक न्याय के एजेंडा पर नये सिरे से बात हो रही है,

दलितों-पिछड़ों की राजनीतिक धाराऐं चुकी हुई सी दीख रही हैं,

सामाजिक न्याय या कहिए बहुजन राजनीति को नये सिरे से गढ़ने की बेचैनी भी सामने आ रही है तो वामपंथ का दक्षिणपंथी धड़ा सीपीआई से लेकर क्रांतिकारी कहे जाने वाले सीपीआई-एमएल तक पतित व साख का संकट झेल रहे दलितों -पिछड़ों की राजनीतिक धाराओं की साख व स्वीकार्यता लौटाने की जद्दोजहद में शामिल हो गया है।

गौर कीजिए,इस दौर में नीला झंडा प्रतिरोध का झंडा बनकर आ चुका है,

नीला रंग प्रतिरोध का रंग बन चुका है,

अंबेडकर का पुनर्पाठ हो रहा है,

सत्ता के गलियारे से अंबेडकर बाहर निकलकर संघर्ष के मैदान में आ चुके हैं,

पिछड़ों के भीतर से भी जय भीम का नारा बुलंद हो रहा है,

जय मंडल और फूले का नाम लेते हुए वे भी मैदान में दलितों के साथ आ रहे हैं!

तो आप कॉमरेड किधर जा रहे हैं?

सचमुच में जय भीम-लाल सलाम के नारे को राजनीतिक व्यवहार में उतारने का उचित समय है,

लेकिन आप तो जय भीम व मंडल की पुरानी धाराओं के साथ रिश्ता गांठने के लिए निकल पड़े हैं!

खैर,सीपीआई और कन्हैया का जय भीम-लाल सलाम का नारा बेगूसराय के लोकसभा सीट को कांग्रेस-राजद के साथ जीतने तक सिमट गया है,

लेकिन भाकपा-माले के पास तो भोजपुर की विरासत है!

उसे तो क्रांतिकारी राजनीतिक कार्यनीति अख्तियार करते हुए दलितों-वंचितों की स्थापित राजनीतिक सीमाओं से पार जाती आकांक्षा,आक्रोश व एजेंडा को जरूर ही संबोधित करते हुए जमीन से उभर रही बिखरी हुई शक्तियों को जोड़ने और वाम-लोकतांत्रिक मोर्चा के पार्ट के बतौर संगठित करने की जद्दोजहद में जाना चाहिए था।

केवल जिग्नेश मेवानी की महाधिवेशन में उपस्थिति व प्रतीकात्मक कोशिश से बात आगे नहीं बढ़ेगी!

जरूरत यह थी कि दलितों-वंचितों के बीच से उभर रही छोटी व बिखरी शक्तियों,महिलाओं के संघर्षों,आदिवासियों की लड़ाईयों और विभिन्न किस्म के आंदोलनों-पहलकदमियों को जोड़ने और व्यापक लोकतांत्रिक एजेंडा के आधार एक प्लेटफॉर्म लाने का मुश्किल व कठोर,लेकिन जरूरी कार्यभार को केन्द्र में रखते हुए ही चुनावी कार्यनीति तय की जाए!

हो सकता है कि दस्तावेज में आपने इस दिशा में कुछ शब्द खर्च किए हों,

लेकिन महाधिवेशन के बाद अपनी पहली पहलकदमी से अपनी प्राथमिकता और महाधिवेशन का संदेश स्पष्ट कर दिया है!

दरहकीकत,आप जिस दिशा में जा रहे हैं,

कार्यनीति का क्रांतिकारी सार ही खत्म नहीं कर रहे हैं,

बल्कि अपनी राजनीति के लोकतांत्रिक अंतर्वस्तु को भी कमजोर कर रहे हैं!

बेशक,इसका असर पार्टी के आंतरिक जीवन और बाहरी व्यवहार में भी पड़ेगा,ही!

सीपीआई तो इसका शानदार उदाहरण है।

बहुतेरे लोग कम्युनिस्ट पार्टियों के भीतर ब्रह्मणवादी प्रवृतियों की मजबूत मौजूदगी की बात करते हैं

और सामाजिक न्याय के एजेंडा पर कम्युनिस्टों की उदासीनता पर बात करते हैं!

बहुतेरे लोग मानते हैं कि दलितों-पिछड़ों की स्थापित राजनीतिक धाराओं ने ब्रह्मणवाद के सामने सरेंडर कर दिया है।

राजनीतिक तौर पर साफ दीखता भी है कि वे ब्रह्मणवादी शक्तियों की राजनीतिक टीम/भाजपा या फिर टीम-कांग्रेस के साथ हैं।

बहुतेरे लोगों का मानना है कि सामाजिक न्याय के संघर्ष की उभरती शक्तियों से दूरी और पतित हो चुकी शक्तियों से नजदीकी कम्युनिस्ट पार्टी के ब्रह्मणवादी-पेट्टी बुर्जुआ चरित्र को ही सामने लाता है! विशालकाय वृक्षों के बीच नन्हें विकसित होते पौधों को आप नहीं देख पा रहे हैं तो आपके क्रांतिकारी लोकतांत्रिक राजनीति को आगे बढ़ाने और

फासीवाद का मुकाबला करने का दावों पर ना भरोसा स्वाभाविक है!

अंत में,तात्कालिकता पर ज्यादा जोर और उसकी सीमाओं में कैद होना,अवसरवाद में डूबने का रास्ता खोलता है!

-रिंकू यादव

खबर (दार) झरोखा

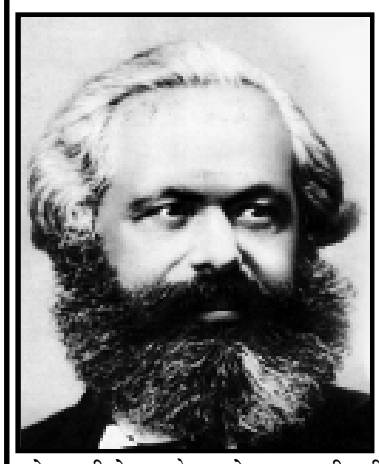

भैया ये मार्क्सवाद क्या है ?

प्रद्युमन यादव

- इसके लिए कुछ आसान सवालों के जवाब देने होंगे। दोगे ?
- हां भैया , बिल्कुल।
- अच्छा , बताओ। हमारे देश में एक तरफ अम्बानी जैसे अमीर हैं तो दूसरी तरफ कल्लन जैसे गरीब हैं। क्या ये अमीर गरीब की खाई मिटनी नहीं चाहिए ?
- बिल्कुल मिटनी चाहिए भैया।
- यही तो है मार्क्सवाद
- ओह !
- अब ये बताओ, कल्लन फैक्ट्री में मजदूरी करता है। वह रोज 5 हज़ार का सामान बनाता है जो मार्किट में 8 हज़ार का बिकता है। 3 हज़ार मालिक को मुनाफा मिलता है। यानी महीने में कुल 90 हज़ार का मुनाफा मालिक को मिलता है। लेकिन कल्लन को तनखाह कितनी मिलती है। 7 हज़ार रुपये। बाकी 83000 मालिक का। क्या कल्लन को अपनी मेहनत के बदले 40000 भी नहीं मिलना चाहिए? अच्छा छोड़ो , 40 नहीं तो उसका चौथाई 10 हज़ार तो मिलना चाहिए। लेकिन नहीं मिलता। उतना भी पाने के लिए उसे हड़ताल करनी पड़ती है जिसमें उसकी 3-4 दिन की पगार कट जाती है। ये सब बंद कर के कल्लन को कम से कम 50, 60 , 70 नहीं तो आधा यानी 40 हज़ार तो पगार मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए ?
- भैया बिल्कुल मिलना चाहिए। यह तो उसका अधिकार है।
- यही तो है मार्क्सवाद।
- अच्छा !
- अब अगले सवाल का जवाब दो। कल्लन को पढ़ाई लिखाई पसंद थी। वह पढ़ने में बहुत तेज था। टीचर बनना चाहता था। लेकिन उसे गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वह फैक्ट्री मज़दूर बन गया। क्या उसे टीचर बनने का अधिकार और इसके लिए सरकार की ओर से सुविधा मिलनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी ?
- भैया , बिल्कुल मिलनी चाहिए थी। सरकार हमारे भले के लिए ही तो होती है।
- बिल्कुल। यही तो है मार्क्सवाद।
- अच्छा अब ये बताओ ।। क्या ये दुनिया ऐसी नहीं होनी चाहिए , जहां न कोई अमीर हो , न कोई गरीब हो । बल्कि सब एक बराबर हो। सबको ढंग का रोटी , कपड़ा , मकान , शिक्षा , पर्यावरण आदि मिले। जहां देश- प्रदेश का बंटवारा न हो , सीमा को लेकर झगड़े न हों। जहां पूरी दुनिया ही अपना घर हो।
- बिल्कुल होना चाहिए भैया। इससे तो दुनिया बेहद खूबसूरत हो जाएगी।
- बस , यही तो है मार्क्सवाद।
- अब ये बताओ कि अगर किसी अच्छे और समाज के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसी दुनिया बनाने के लिए लड़ना भिड़ना पड़े , आंदोलन करना पड़े , विरोध करना पड़े तो क्या उसे पीछे हट जाना चाहिए ? या डटे रहना चाहिए।
- भैया डटे रहना चाहिए। मैं तो कहता हूं , जान लगा देनी चाहिए।
- तुम समझ गए। यही तो है मार्क्सवाद।
- भैया मार्क्सवाद तो बहुत अच्छी चीज है। फिर लोग इसे बुरा क्यों समझते हैं ? आम लोग इससे दूर क्यों हैं ?
- वो इसलिए हैं क्योंकि अमीर बुरे हैं। और उनसे भी बुरे हैं मार्क्सवादी। वो समाज के हित की बजाय अपना हित साधने में लगे हैं। उन्हें विद्वान और धनवान बनना है। उन्हें मार्क्सवाद के नाम पर कल्लन का वोट हासिल कर सत्ता चाहिए। उन्होंने एक खूबसूरत विचार को धंधा बना दिया है और अब वो भी अमीरों की तरह फलफूल रहे हैं। इसीलिए।
- और कल्लन ? कल्लन क्या कर रहा है।
- वो तो इन सब बातों से अनजान है। वो आज भी वहीं फैक्ट्री में मजूरी कर रहा है।

कहने को तो यह मात्र एक सौदा है लेकिन फ्लिपकार्ट ओर वालमार्ट की डील भारत के रीटेल मार्केट की तस्वीर पूरी तरह से बदल कर रख सकती है

गिरीश मालवीय

पूरी दुनिया मे वॉलमार्ट लोकल मार्केट को बर्बाद करने के लिए कुख्यात रहा है। वॉलमार्ट का इतिहास यह रहा है कि वो बहुत कम कीमत पर सामान बेचकर छोटे-मोटे कारोबारियों को अपने रास्ते से हटा देती है। उसके पास न पैसे की कमी है ओर न राजनीतिक संपर्कों की, दुनियाभर के बाज़ारों में उसकी सीधी पहुँच है। ऐसे में वो दूसरे देशों का सस्ता सामान विशेषकर चीन से भारत में डंप कर चुटकियों में देश के लघु ओर मध्यम श्रेणी के उद्योगों को बर्बाद कर सकता है।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक अरुण ओझा का अनुमान बिल्कुल सच है कि इस सौदे से छोटे कारोबारियों का कारोबार चौपट हो जाएगा और इससे देशभर में 20-22 करोड़ परिवार प्रभावित होंगे। वालमार्ट और फ्लिपकार्ट के सौदे से वालमार्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के जरिए भारत के बाजार पर इन विदेशी कंपनीयो का प्रभुत्व कायम हो जाएगा।

अभी वालमार्ट देश के नौ राज्यों के 19 शहरों में 21 होलसेल स्टोर खोल चुकी है ओर 50 नये स्टोर्स खोलने की वह घोषणा कर चुकी है। इस डील के बाद आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि भारत के रिटेल मार्केट कैप पर इस कम्पनी का कितना बड़ा कब्जा होने जा रहा है।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्विनी महाजन कहते हैं कि विदेशी निवेश इक्विटी के जरिए होना चाहिए लेकिन रिटेल कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं हैं।

उनकी चिंता बिल्कुल जायज है क्योंकि ई कॉमर्स के क्षेत्र में कोई स्पष्ट नियम अभी तक नही बनाए गए हैं। जिसकी जैसी मर्जी होती है वह अपने हिसाब से किसी भी ऑनलाइन सेल लगा लेता है। फ्लिपकार्ट सिर्फ कहने के लिए एक प्लैटफॉर्म है लेकिन वह जिस तरह से छोटे व्यापारियों का धंधा छीन रहा है वह देश मे बेकारी की समस्या को ओर गहनतर करता जा रहा है।

मूल रूप से ई कॉमर्स प्लेटफार्म में बिजनेस के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गयी थी। एफडीआई पॉलिसी 2016 की धारा 2,3 की उपधारा 9 कहती हैं कि ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस मॉडल सिर्फ तकनीकी प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगा और किसी भी रूप में सीधे अथवा अप्रत्यक्ष रुप से कीमतों को प्रभावित नहीं करेगा और न ही कोई असमान प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाएगा। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है सब अच्छी तरह से जानते हैं।

खुदरा कारोबारियों का संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) भी अब खुलकर इस सौदे के विरोध में उतर पड़ा है। उसका कहना है ''इस सौदे को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इससे ई-कामर्स क्षेत्र में लागत से भी कम दाम पर कारोबार करने और बाजार बिगाड़ने वाले मनमाने तरीके से कीमत तय करने को बढ़ावा मिलेगा जो पहले ही गलत व्यापारिक तरीकों की जकड़ में है।''

लेकिन बात सिर्फ छोटे व्यापारियों के नुकसान तक ही सीमित नही है। इस सौदे में सरकारी खजाने का भी बड़ा नुकसान होता दिख रहा है , ...इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फ्लिपकार्ट कंपनी को ईमेल भेजकर कहा है कि उसकी संपत्ति भारत में है, इसलिए टैक्स की देनदारी बनती है। चूँकि भारत में मौजूद संपत्ति का सौदा हो रहा है इसलिए विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा. विदेशी भी भारत में मौजूद संपत्ति का सौदा करे तो ये टैक्स लगता है। अनुमान है कि इस सौदे पर 10-20 फीसदी तक विदहोल्डिंग टैक्स लग सकता है।

लेकिन इस सौदे में अभी तक किसी भी प्रकार की टैक्स लायबिलिटी की बात कम्पनी ने नही मानी है। अश्विनी महाजन इस सौदे के बारे में कह रहे है कि डील सिंगापुर में हुई, बेंगलुरु में अनाउंस हो रही है और दिल्ली में अप्रूवल लिया जा रहा है, इससे भारत में एक भी पैसा नहीं आएगा।

लिख कर रख लीजिए यह सौदा थोड़े दिनों में छोटे और मझोले व्यापार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा क्योंकि मोदी सरकार ने उन्हें मृत्युशैया तक पुहचाने मे कोई कोर कसर बाकी तो पहले ही नही छोड़ी है।